IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्तमान भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय मूल्य

डॉ. भावना भदौरिया
प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
शा. हमीदिया कला एवं वाणिज्य महावि.
भोपाल (म.प्र.)

शोध सरांश

1947 के स्वाधीनता आन्दोलन में राजनीति एक आदर्श अभियान थी। परंतु धीरे–धीरे भारतीय राजनीति वर्तमान में व्यवसाय और व्यापार बन गई है।

बिना सिद्धांत की राजनीति के कारण ही हमारे राष्ट्रीय मूल्यों का क्षरण हुआ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये चुनौती है। साम्प्रदायिक भावनायें, हिंसा, लालच, चुनावी व्यय गैर कानूनी धनशक्ति इत्यादि चीजों ने राजनीति का प्रदुषित किया है।

उपरोक्त सभी कारणों में सीमायें तय करके राजनीतिक मूल्यों की रक्षा की जा सकती है।

प्रस्तावना–

1947 के स्वाधीनता आन्दोलन में राजनीति एक आदर्श अभियान था। लोगों ने राजनीति अपने स्वार्थ के लिये नहीं चुनी थी बल्कि देश के लिये कुछ करने की ललक तथा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की निष्ठा थी। वह विदेशी शासन से आजादी चाहते थे। उस समय उच्च आर्दशों वाले नेता सिर्फ भारतीय राजनीति को प्रभावित ही नहीं करते थे वरन देश व समाज को भी प्रेरित करते थे। जैसे– महात्माँ गाँधी, सुभाषचंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, पटेल, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब्दुल कलाम आजाद आदि नामों को आज भी राष्ट्रीय मूल्यों के लिये याद किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय मूल्यों का मूल भाव धीरे–धीरे समाप्त होने लगा और भारतीय राजनीति वर्तमान में व्यापार व व्यवसाय बनकर रह गई।

समस्या–

भारतीय राजनीति में आई मूल्यों की कमी के मुख्य कारणों का पहचानने की आवश्यकता है तथा समाधान के लिये साधन ढुंढने की जरूरत है। भारतीय राजनीति धर्म, जाति व क्षेत्रों के बीच नफरत में घिरकर रह गई है। चुनाव के पूर्व व चुनाव के बाद की सम्पूर्ण संरचना भेदभाव व राजनीतिक विखण्डन को बढ़ावा देती है।

मतदान का आधार भय है न कि आशा। एक दूसरे दल को सत्ता से दूर रखने की इच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी या दल को चुनने से कहीं अधिक होती है। इस राजनीतिक मतदान से साम्प्रदायिक भावनायें, लालच खासदल के प्रति गुस्सा चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप आरक्षण का उदय, पहचान की राजनीति, हिंसा करवाना एवं अस्थिरता बहुत ही साधारण नियम बन गया है। नागरिकों का वर्गीकरण कर मूल निवासी व बाहर से आने वाले नाम देकर उनके बीच द्वेष उत्पन्न कर भारत के विचार की हत्या कर देते हैं।

इतना ही नहीं राजनीति को व्यापार के रूप में लिया जा रहा है इसीलिये फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट निर्वाचन प्रणाली (जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को विजयी माना जाता है।) गैर कानूनी धन शक्ति, अधिक चुनानी व्यय, पैसे व शराब के माध्यम से वोट खरीदे जाते हैं।

भारत में आजादी के बाद ट्रांसपेरेंसी इंन्टरनेशनल एन्युअल रिपोर्ट जो देशों को भ्रष्टाचार के आधार पर पर सूची बद्ध करती है। उसमें भारत शीर्ष स्थान पर है और दूसरी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानव विकास सूची पर भारत सबसे नीचे है।

राजनीति व राजनेताओं को बीच मूल्यों का क्षरण इतनी तेजगति से हो रहा है। कि पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही उससे आच्छादित है। मूल्यों का आभाव वकील, जज, शिक्षक, डॉक्टर सभी में समान रूप से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि मीडिया में भी जो दिनभर राजनीति व सरकार में भ्रष्टाचार का खुलासा करती रहती है।

यह लोकतंत्र के लिये ही खतरा नहीं वरन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी चुनौती है। क्योंकि हमारी व्यवस्था में भ्रष्ट तत्व आसानी से राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं।

वर्तमान में बिना सिद्धांत के राजनीति, बिना नैतिकता के व्यापार बिना कार्य के सम्पत्ति बिना चरित्र के शिक्षा, बिना मानवता के विज्ञान चेतनता के बिना आनंद त्याग के बिना पूजा हमारे नागरिकों के आर्दश रहेंगे तो हम चाह कर भी राज्य व समाज में मूल्यों की स्थापना नहीं कर सकेंगे।

लोकतांत्रिक मूल्यों का अर्थ सिर्फ अपना नेता चुन लेना ही नहीं होता वरन् सच्चे अर्थों में विरोधियों को भी अपनी बात रखने का अधिकार देना, भावनात्मक प्रलाप के स्थान पर चर्चा और उचित वाद–विवाद के आधार पर अपनी बात रखने की अनुमति लोकतंत्र देता है जब तक एक आम सहमति पर न पहुँचा जाये।

यदि हम राष्ट्रीय मूल्यों के क्षरण के संकट को कम करना चाहते हैं तो हमें हर पेशे में एम.क्यू. (नैतिक मूल्य) और एस.क्यू. (आध्यात्मिक मूल्य) का पालन करना होगा खासतौर पर नेतृत्व शील पदों पर।

राष्ट्रीय मूल्य किसी व्यक्ति, किसी संस्थान या कुछ लोगों या संस्थानों के समूह का संरक्षण नहीं है यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह देश को और बेहतर बनाने के लिये उन प्रवृत्तियों को संरक्षित करे, जो मूल्यों को बतलाती, और प्रभावित करती है एवं सुनिश्चित भी करती है कि हम विश्व के मंच पर एक महान देश के नागरिक रहें। परंतु कमजोरों का संरक्षण कैसे होगा ? शक्तिशाली के खिलाफ कौन बोलेगा ? अकेली आवाज का साथ कौन देगा ? चापलूसी पर रोक कौन लगायेगा ? रिश्वत ने देने के कारण कार्य की हानि की क्षति पूर्ति कौन करेगा?

यह प्रश्न मन में चिंता उत्पन्न कहते हैं। ऐसी तमाम चिन्ताओं के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। इसमें बहुत सी व्यवहारिक समस्याऐं हो सकती हैं। परंतु यदि बदलाव लाना है तो एक किनारे पर खड़े होकर व्यवस्था को कोसने से काम नहीं चलेगा वरन अपने अंदर बदलाव लाना होगा। उदाहरण के लिये हम सदा मिलकर यह तय करें कि कोई रिश्वत नहीं लेगा– और न देगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई आर्थिक सुविधा नहीं होगी।

सुझाव–

हमें राजनीति मूल्यों की स्थापना के लिये कुछ सुझाव पर अमल करना होगा–

1. एक बेहतर दल–बदल कानून बनाना होगा जिससे जनता की भावनाओं को ठेस न पहुँचे।
2. राजनीति में अपराधीकरण की जाँचकर अपराधियों को कानून, निर्माता बनने से रोकना होगा।
3. मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगानी होगी।
4. निर्वाचन याचिकाओं का त्वरित निष्पादन करना होगा।
5. नकारात्मक मतदान से परिचय होने पर मतदाता राजनीतिक दलों के द्वारा नामित प्रत्याशियों के प्रति अपना विरोध दर्ज करा सके।
6. दुर्व्यवहार के मामले में निर्वाचित प्रत्याशी को वापिस बुलाना।
7. किसी खास पार्टी के पक्ष में मीडिया को माहौल बनाने से रोकना।
8. चुनावी व्यय के संबंध में सीमाऐं तय करना।
9. धर्म, क्षेत्र, जाति का दुरूपयोग करने पर दण्ड का प्रावधान।
10. वर्तमान फार्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट प्रणाली (जिसको ज्यादा वोट मिले वहीं विजयी प्रणाली) के बदले बेहतर चुनाव प्रणाली जैसे सूची प्रणाली को अपनाना इत्यादि।

उपंसहार–

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है। कि भारतीय राजनीति की यदि साफ–सुथरी छवि बनानी है तो ऊपर दिये गये सुझावों पर अमल करना होगा तथा अध्यात्मिक विरासत एवं नैतिक मूल्यों को शामिल करके राष्ट्रीय कल्याण के लिये न्याय वितरण के लिये एक प्रभावी और मूल्य आधारित व्यवस्था का निर्माण करें।

संदर्भ सूची–

1. आधुनिक भारत– सुमित सरकार
2. भारतीय राजव्यवस्था– डॉ. सुभाष कश्यप
3. मूल्यों की पुनः स्थापना– ई.जी. घरन, भरत वख्लू
4. भारतीय राजनीति– एस.सी.सिंघल
5. जनसत्ता
6. इण्डिया टुडे